आलोक मेहता

लाल आंखें नहीं देखतीं कड़वा सच

केरल और बंगाल में अपने पाप छिपाने के लिए कम्युनिस्टों ने मीडिया पर बोला हमला

सत्ता के नशे में रहने वाले हर नेता को कड़वा सच बोलने वाला दुश्मन दिखता है। अब तक नरेंद्र मोदी जैसे कट्टरपंथी नेता मीडिया को लानत भेजते थे लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के कथित प्रगतिशील कम्युनिस्ट एक कदम आगे बढ़कर सभी आलोचक अखबारों और पत्रकारों को राष्ट्र-विरोधी तथा अमेरिकी एजेंसी सी.आई.ए. से जुड़ा 'मीडिया सिंडीकेट' बताने जैसी घृणित टिप्पणी करने लगे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन वी.एस. अच्युतानंदन केरल के सबसे प्रतिष्ठित, निष्पक्ष और लोकप्रिय प्रकाशन समूह के *मलयाला मनोरमा, दीपिका* तथा *मातृभूमि* जैसे पत्र-पत्रिकाओं पर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अमेरिकी धन लेने तथा कम्युनिस्टों को सत्ता में न आने देने के आरोप लगा रहे हैं। केरल में अभी तो चुनाव भी नहीं हो रहे। वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा उनके अन्य सहयोगी सत्ता में हैं। पश्चिम बंगाल में 30 साल राज करने के बावजूद गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था या सिर पर मैला ढोने जैसी पुरानी सामाजिक मजबूरियों का निदान कम्युनिस्ट नहीं कर पाए। केरल में उन्हें लगभग 5 साल छोड़कर जनता पुन: अवसर देती रही है लेकिन कम्युनिस्टों ने गरीब जनता को राहत दे सकने वाले समुचित कदम नहीं उठाए हैं। भाजपा, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह केरल और पश्चिम बंगाल के कई मंत्री भ्रष्टाचार, ठेकों में हिस्सेदारी, अपराधियों और पुलिस गठजोड़ के संरक्षण में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से फंसे हुए हैं। लाल झंडा फहराते-फहराते कम्युनिस्टों की आंखें संभवत: इतनी लाल हो चुकी हैं कि उन्हें श्याम-श्वेत (ब्लैक एंड व्हाइट) सच्चे तथ्य भी परदेसी लगते हैं। केरल में सरकार की असफलताओं के कारण बढ़ रही समस्याओं को रिपोर्ट, तथ्यात्मक टिप्पणियां छापने वाले पत्र-पत्रिकाओं को राष्ट्र-विरोधी बताने के लिए अच्युतानंदन ने एक अमेरिकी राजनयिक की 40 साल पुरानी पुस्तक को आधार बनाया है। इस अमेरिकी राजनयिक ने दावा किया था कि 'एक बार केरल में तथा एक बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को सत्ता में आने से रोकने के लिए अमेरिकियों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी तत्कालीन प्रमुख इंदिरा गांधी को धन दिया था।' केरल के कामरेड को यह किताब याद आ गई लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वारा 1969 से 1984 तक सी.आई.ए. के षड्यंत्रों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का एक पन्ना भी याद नहीं रहा। वह इस बात को भी भूल गए कि कम्युनिस्टों ने तब से आज तक मौका आने पर केंद्र में कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़कर अपनी आबरू बचाई है। सी.आई.ए. और के.जी.बी. के षड्यंत्रों की पुष्टि आसानी से नहीं होती लेकिन देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारत में अस्थिरता तथा इंदिरा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सी.आई.ए. को भी दोषी मानते हैं। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार पाकिस्तान के सैनिक आक्रमण के साथ राष्ट्रपति निक्सन के अन्य तरह के हमले और अमेरिका के सातवें बेड़े से निपट रही थी, उस समय का कोई अमेरिकी एजेंट चरित्र-हत्या के लिए क्या इंदिरा गांधी पर धन लेने का आरोप नहीं लगा सकता था? फिर कम्युनिस्टों को उनसे और कांग्रेस पार्टी से इतनी नफरत थी तो 1977 में जनता पार्टी या 1984 और 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उसका साथ देने वाले मीडिया के विरुद्ध आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा?

भाजपा, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह केरल और बंगाल के कई मंत्री भ्रष्टाचार, ठेकों में हिस्सेदारी, अपराधियों और पुलिस गठजोड़ के संरक्षण में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से फंसे हुए हैं।

दूसरा सवाल यह उठता है कि भारत के कम्युनिस्ट कितने दूध के धुले हैं। ज्योति बसु किसी कांग्रेसी या पत्रकार को काबू में नहीं रख सकते थे लेकिन अपने परिवार के उन सदस्यों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते थे जो डॉलर कमाने के चक्कर में अमेरिका तथा यूरोप में पूंजीपतियों और अमेरिकी शासकों की आरती उतारने में किसी से पीछे नहीं हैं। केरल और पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकारों के मंत्री अमेरिकी पूंजी निवेश के लिए वाशिंगटन-न्यूयॉर्क के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि अमेरिकी शासक या सी.आई.ए. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये भी धन बांटती है? कामरेड अच्युतानंदन और कामरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास यदि किसी प्रकाशन समूह, संपादक या पत्रकार द्वारा गैर कानूनी ढंग से अमेरिकी धन पाने के पर्याप्त प्रमाण हैं तो वे कानूनी आधार पर उन्हें दंडित क्यों नहीं करवाते? अब तो सूचना का अधिकार केवल पत्रकारों के पास नहीं है। लाल झंडा थामे उनका कोई कामरेड 10 रुपये जमा कर किसी भी प्रकाशक या संपादक के बैंक खाते और आयकर विभाग से ब्यौरा लेकर अमेरिकी फंडिंग का भंडाफोड़ कर सकता है? इसी तरह क्या पारदर्शिता का तकाजा यह नहीं है कि इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी तक के सत्ता-काल में कई कामरेडों की मास्को, बीजिंग में इलाज या अन्य सहायता के लिए यात्राओं, उन पर हुए खर्चों एवं कम्युनिस्ट समर्थित संगठनों को मिले फंड का पूरा विवरण भी सार्वजनिक किया जाए। निश्चित रूप से हिंदू या मुस्लिम कट्टरपंथियों को जाने-अनजाने संगठनों के नाम पर मिलने वाले विदेशी धन पर अंकुश होना चाहिए लेकिन कम्युनिस्टों की छत्रछाया में पलने वाले संगठनों का हिसाब-किताब भी तो देखा जाना चाहिए। केवल प्रकाश करात और सीताराम येचुरी की ईमानदार छवि का सहारा लेकर कम्युनिस्ट शासित राज्यों में गुलछर्रे उड़ाने वालों, न्यायपालिका तथा मीडिया पर हमला करने वाले भ्रष्ट और निकम्मे नेताओं का पर्दाफाश कैसे अनुचित माना जा सकता है? यों कम्युनिस्टों के अनर्गल आरोपों या सरकारी दबाव से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मीडिया विचलित नहीं होने वाला है।

कम्युनिस्टों और श्रमिक संगठनों के कुछ नेताओं पर अमेरिकी छाया के संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अमेरिका तथा उसकी सी.आई.ए. द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जमाने के लिए कई दशकों से विभिन्न देशों में कुछ कथित कम्युनिस्टों और श्रमिक नेताओं को पटाने, उन्हें आर्थिक मदद देने के प्रयास होते रहे हैं। कई देशों में रह चुके अमेरिकी राजनयिक फिलीप कैजर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, 'अमेरिकी दूतावासों में तैनात श्रमिक अटैची का दायित्व श्रम आंदोलन से जुड़े नेताओं के संपर्क में रहकर उन्हें अमेरिकी हितों के लिए जोड़ना रहा है।' रूस या पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासित देशों में सी.आई.ए. ने 'कम्युनिस्टों' को ही अपने लिए जासूसों या जयचंदों की तरह इस्तेमाल कर सत्ता परिवर्तनों के लिए उपयोग किया। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि सी.आई.ए., एफ.बी.आई. और ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी एम.आई.-5 भी अमेरिका तथा ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टियों को फंडिंग करती रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि देर-सबेर केरल या बंगाल के कामरेडों की ऐसी ही पोल खुल जाए। इसलिए किसी एक दल, संगठन या मीडिया को दोषी ठहराने से पहले कम्युनिस्टों को अपने घर-आंगन तथा संरक्षक विदेशी कम्युनिस्टों का ताजा इतिहास समझ लेना चाहिए। ●